

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 608] No. 608] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 1997/कार्तिक 6, 1919 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 1997/KARTIKA 6, 1919

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1997

का०आ० 752(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदेत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, न्यायमूर्ति श्री के०एस० पेरीपूरनम्, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधींश का, 10 अक्तूबर, 1997 से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा॰सं॰ 1(3)/96-सी॰पी॰यू॰] कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 1997

S.O.752 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government in consultation with the Chief Justice of India hereby appoints Mr. Justice K. S. Paripooranan, Retired Judge of the Supreme Court as the President of National Consumer Disputes Redressal Commission with effect on and from the 10th day of October, 1997.

[F.No. 1(3) /96-CPU]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser,